ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights **28 May, 2020**

Smt Sonia Gandhi addressed the people via video message today (First Video Message).

श्रीमती सोनिया गाँधी ने कहा - मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी-रोटी, रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे-प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकडों-हजारों किलोमीटर पैदल चल कर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं।

करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखानें बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ।

पहले दिन से ही, मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थ-शास्त्रियों ने, समाज-शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार-बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़ कर घाव पर मरहम लगाने का है, मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। न जाने क्यों केंद्र सरकार यह बात समझने और लागू करने से लगातार इंकार कर रही है।

इसलिए, कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खज़ाने का ताला खोलिए और ज़रूरत मंदों को राहत दीजिये। हर परिवार को छः महीने के लिए 7,500 ₹ प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 ₹ फौरन दें। मज़दूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम कर घर पहुंचाईये और उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम भी करें और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गाँधी मनरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससें गांव में ही रोज़गार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिये, ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचें और देश की तरक्की भी हो।

आज इसी कड़ी में देशभर से कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर सरकार के सामने यह मांगें दोहरा रहे है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, अपनी परेशानी साझा कीजिए ताकि हम आपकी आवाज को और बुलंद कर सकें।

संकट की इस घड़ी में हम सब हर देशवासी के साथ हैं और मिलकर इन मुश्किल हालातों पर अवश्य जीत हासिल करेंगे।

जय हिंद!

Sd/-
(Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights **28 May, 2020**

Smt Sonia Gandhi addressed the people via video message today (Second Video Message).

श्रीमती सोनिया गाँधी ने कहा - मेरे प्यारे भाईयो और बहनों, मुझे आपसे एक बार फिर बात करने की जरूरत महसूस हुई। आज सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। हमारे देश में जो इस महामारी के खिलाफ कदम लिए है और जो कदम लेने चाहिये, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूं।

लॉकडाउन जरूरी था, यह मान के चलिये, मगर क्या यह भी जरूरी था कि देश की जनता को सिर्फ चार घंटे की मोहलत दी जाए? क्या सरकार ने सोचा था कि जब कारखानों के, जब दुकानों के मालिक अपने दरवाजे बंद कर देंगे, तो मज़दूर का क्या होगा? क्या सरकार ने सोचा कि सड़क पर खड़े बेरोजगार मजदूर क्या कमायेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जियेंगे, कहाँ जाएंगे? वो गरीब जिनसे कोरोना और लॉकडाउन ने जीने का हर सहारा छीन लिया है, लगता है इन लोगों का ध्यान शुरू से ही नहीं रहा।

किसी भी सरकार की सच्ची और सीधी परीक्षा यही होती है कि वे समाज के निर्धन और निर्बल के लिये क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी की माँग है कि सबसे पहले बेरोजगार और गरीब लोगों को राहत दी जाए।

जब कांग्रेस पाटी ने गरीब माइग्रेंट को फ्री रेल टिकट देने का ऐलान किया, तभी केन्द्रीय सरकार ने 85 प्रतिशत टिकट का दाम भरने की घोषणा की । यह अलग बात है की आज भी जहाँ हमारी सरकारें हैं या काँग्रेस के सहयोगियों की सरकारें है, वहाँ राज्य सरकार माइग्रेंट मज़दूर को फ्री टिकट दे रही है - मगर केन्द्र के 85 प्रतिशत का अभी तक कोई पता नहीं है। ऊपर से रेलों की कमी के कारण आपने खुद देखा है किस तरह मज़दूर अपने पूरे परिवार को ट्रक, टेम्पों, साईकल पर, हाइवेज पर जा रहें हैं। उनकी हालत देखकर किसी का भी दिल कांप उठता। अगर कोई राहत पहुँचाने की कोशिश भी करे तो उसे रोका जाता है, जैसे हाल में भाजपा सरकार ने किसी न किसी बहाने पर कांग्रेस की बसों को रोका है।

मनरेगा में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करें, बहुत ही जरूरी है, ताकि गाँव में ही काम मिल सके, छोटे और लघु उघोगों को आर्थिक राहत मुहैया कराऐं ताकि करोड़ों नौकरियाँ भी बचें और देश की तरक्की भी हो।

बेशक देश की आर्थिक समस्या को सुधारने के लिये सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) को पूरा सहयोग और समर्थन दें - ताकि रोजगार तेज़ी से बढ़े। उन्हें सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए एक लाख करोड़ की मदद दे सकती है। यह भी उतना ही ज़रूरी है कि इस हालात में हरेक बेरोजगार और गरीब व्यक्ति को कम से कम 10 किलो मुफ्त राशन बिना राशन कार्ड के दिया जाये। और इसके अलावा अगले 6 महीने तक उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर द्वारा 7,500 रुपये डाले जायें।

कोई सवाल उठा सकता है कि इस काम के लिये पैसा कहाँ से आएगा। सच तो यह है कि पैसे की कोई कमी नही है, उसका सिर्फ इस्तेमाल सही होना चाहिये। वो बीस हज़ार करोड़ रुपये, जो सरकार ने नई दिल्ली की सेंट्रल विस्टा की सजावट के लिये रखे हैं वह उन लोगों की मदद के लिये लगाया जा सकता है जो भूखे-प्यासे सड़कों पर चल रहे हैं।

सरकार का दावा है कि वह जीडीपी का 10 प्रतिशत देश की जनता पर आई इस समस्या के लिये दे रही है। लेकिन ध्यान से इनके आंकड़ें देखे जाएं तो सीधा दिखेगा की सिर्फ 1 प्रतिशत दिया गया है।

मैं यह मांगें आपके सामने रख रही हूँ। आपकी बात तो सरकार को सुननी ही पड़ेगी। मैं समझती हूँ आपके मन में गरीबों और बेराज़गारों के लिये, मज़दूरों और किसानों के लिये, इस संकट की घड़ी में कितना दर्द है। इसलिये आप साफ़ और ऊँची आवाज़ मे सरकार से पूछें - जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो होना चाहिये वह क्यों नहीं हो रहा है, और अगर होगा तो कब होगा।

धन्यवाद, जय हिन्द!

Sd/-
(Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC